जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 31 संख्याः 40 प्रभात अजमेर, मंगलवार 8 सितम्बर, 2026 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

जर्मनी के चुनाव में ''नैशनलिज़्म'' की पुरजोर ढंग से वापसी ने सभी को चौंका दिया है

अब तक, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जर्मनी की राजनीति यहूदियों पर हुए अत्याचार से उत्पन्न देशव्यापी ग्लानि पर आधारित रहती थी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। क्या इतिहास, यानी किसी समुदाय की सामूहिक याद के तौर पर, आज के चुनाव में कोई भूमिका निभाता है? हां, जर्मनी में पिछले रविवार हुए एक महत्वपूर्ण चुनाव के नतीजों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है।

एक कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, यानी एएफडी ने देश के एक राज्य में हुए चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत से पूरे यूरोपीय संघ में चिंता की लहर दौड़ गई है और रूस में खुशी की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इसकी लहरें अटलांटिक पार अमेरिका तक पहुंच गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चुनाव के नतीजों का जिक्र किया है।

यूरोप हैरान है और इस बात पर गंभीरता से विचार कर रहा है कि क्या यह जर्मन राष्ट्रवाद के फिर से उभरने की एक छोटी सी शुरुआत है। हो सकता है कि नाज़ी दौर के अनुभव के कारण यूरोप अब भी एक तरह की मानसिक बेचैनी से गुजर रहा हो।

- पर, वर्तमान चुनाव में राजनीति का आधार ग्लानि को पीछे छोड़कर जर्मनी के अन्य समृद्ध इतिहास की ओर मुड़ा है।
- ऐसा लग रहा है, हिटलर की ज्यादतियों की याददाश्त को धूमिल कर जर्मनवासी बिस्मार्क की ओर देख रहे हैं।
- इस मानसिक बदलाव में, जर्मनीवासी अपने देश को ''एक विचारकों व कवियों'' के देश के रूप में जानना व याद रखना चाहता हैं।
- चाहे, आधुनिक जर्मनी, अधिक समृद्ध है। पर, नई पीढ़ी शायद कुछ कम समृद्धि बर्दाश्त करने को तैयार है, पर, अपनी ''जर्मननैस'' (जर्मनत्व) को बरकरार रखने में ज्यादा खुशी महसूस करना चाहती है।

एएफडी ने रविवार को अपने सबसे नए प्रतिद्वंद्वी कंज़र्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी, यानी सीडीयू पर जोरदार चुनावी जीत हासिल की है, जो अपने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी पार्टनर, एसपीडी के साथ गठबंधन में फैडरल लैवल पर शासन करती है।

एएफडी जर्मनी को हिटलर के जर्मनी के बजाय, ओटो फॉन बिस्मार्क के जर्मनी के तौर पर देखने को बढ़ावा दे रही है। वह उन्नीसवीं सदी के जर्मनी और जर्मनी एकता के इतिहास को पढ़ाने की बात कर रही है, जिसमें हिटलर के शासन और राष्ट्रीय समाजवाद, उत्पीड़न और युद्ध की किसी भी गलती को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

बिस्मार्क ने अनेक छोटे राज्यों और रियासतों को एकजुट करके उस देश की नींव रखी, जो बाद में बीसवीं सदी में जर्मनी बना। पार्टी ''ज्यादा बिस्मार्क और कम हिटलर'' की बात कर रही है।

नाज़ी शासन को उसके अत्याचारों से बरी नहीं करते हुए, एएफडी उन लोगों की भावनाओं को सामने रख रही है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए हैं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

छह विधानसभा व एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव 6 अक्टूबर को

नई दिल्ली, 07 सितंबर। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा सीटों तथा असम की एक लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन छह सीटों पर मतदान छह अक्टूबर को होगा, जबकि मतगणना नौ अक्टूबर को की जाएगी। चुनाव प्रक्रिया 11 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।

- मतगणना 9 अक्टूबर को होगी।

आयोग के अनुसार, तमिलनाडु की मदुरांतकम (अनुसूचित जाति) और धारापुरम (अनुसूचित जाति) विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। पुदुचेरी की थट्टानचावडी विधानसभा सीट तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर भी मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा असम की नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इन सभी सीटों पर रिक्तियां संबंधित निर्वाचित सदस्यों के इस्तीफे के कारण हुई हैं।

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की अधिसूचना नौ सितंबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 19 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। मतदान छह अक्टूबर और मतगणना नौ अक्टूबर को होगी।

'लगता है आप मेरे रिटायरमैंट का इंतजार कर रहे हैं, ''डेट-पर-डेट'' मांग कर'

सुप्रीम कोर्ट ने ''हाई पावर्ड'' कमेटी की, रिपोर्ट देने के लिए लंबी तारीख की अर्ज़ी ठुकराई और तीस नवंबर को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को सवाल उठाया कि क्या अरावली की पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान परिभाषा तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी उनके रिटायरमेंट का इंतजार कर रही है। अदालत ने समिति की, छह महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग ठुकराते हुए उसे 30 नवंबर तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

सीजेआई ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, ''उन्हें सीधे ही मेरे रिटायरमेंट के बाद की तारीख मांगनी चाहिए थी... ऐसा लगता है कि वे मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। सीजेआई सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 को अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली बैंच, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल थे, ने अपने आदेश में कहा,

- जैसा कि विदित ही है, अरावली पर्वत श्रृंखला को चिह्नित व परिभाषित करने के लिए, एक हाई-पावर्ड कमेटी गठित की गई है, जिसे किन्हीं कारणों से अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश करने में काफी हिचकिचाहट हो रही है।

उच्चस्तरीय समिति ने पहली ही बार में 28 फरवरी 2027 तक समय बढ़ाने की मांग की है। हम इस मांग को खारिज करते हैं। उच्चस्तरीय समिति को दिन-रात काम करने और 30 नवंबर 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाता है। हम स्पष्ट करते हैं कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा।''

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अरावली की नई परिभाषा तय करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने तब शुरू कराया था, जब उसने नवंबर 2025 के अपने ही उस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें एक विवादित परिभाषा को स्वीकार किया गया था। पर्यावरणविदों को आशंका थी कि इस परिभाषा के कारण, पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील अरावली क्षेत्र का बड़ा हिस्सा खनन के लिए असुरक्षित हो सकता है।

केन्द्र द्वारा पहले गठित समिति ने प्रस्ताव दिया था कि अरावली जिलों में स्थानीय भू-स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली किसी भू-आकृति को अरावली पहाड़ी माना जाएगा। ऐसी दो या उससे अधिक पहाड़ियां, जो एक-दूसरे से 500 मीटर के भीतर होंगी, अरावली पर्वतमाला का हिस्सा मानी जाएंगी।

इस परिभाषा को लेकर चिंता जताई गई थी कि केवल ऊंचाई के आधार पर तय किए गए इस मानदंड से अनेक छोटी पहाड़ियां और टीले अरावली पर्वतमाला से बाहर हो सकते हैं, जो व्यापक पारिस्थितिक क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का स्वत: संज्ञान लिया और 29 दिसंबर 2025 को अपने पहले के आदेश को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी ने राज्यों के प्रभारी क्यों बदले?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। कांग्रेस में 5 सितंबर को हुए संगठनात्मक फेरबदल में केवल छह राज्यों को शामिल किया गया है, लेकिन प्रभारियों के चयन से पार्टी के अंदर नेताओं की स्थिति के बारे में काफी कुछ पता चलता है। छह राज्यों के प्रभारियों को बदलने के पीछे हाईकमान का अपने ही नेताओं के बारे में एक आकलन है कि वह किस पर भरोसा करता है, किसे आजमाना चाहता है, किसे एक और मौका दिया गया है और किसे दूसरी पंक्ति से उठाकर राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है।

सबसे महत्वपूर्ण नियुक्ति छत्तीसगढ़ से पंजाब भेजे गए सचिन पायलट की है। यह उनके लिए पदोन्नति भी है और परीक्षा भी। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 16 मार्च 2027 को खत्म हो रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उत्तर भारत के उन कुछ बड़े राज्यों में से एक है, जहां कांग्रेस के सत्ता में आने की वास्तविक संभावना है।

- अधिकतर तो परिवर्तन शाबाशी का प्रतीक, पर बघेल के पंजाब से आसाम स्थानांतरण में हाईकमान की उनके प्रति कुछ ''नाराज़गी'' व निराशा की झलक दिखती है।

पंजाब में ताजा लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच है, जो अब चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। इस मतभेद के कारण पहले ही अलग-अलग गुट बन चुके हैं, वड़िंग को हटाने की मांग उठ चुकी है।

हाईकमान के लिए मुश्किल यह है कि वड़िंग और चन्नी दोनों ही राहुल गांधी के पसंदीदा नेता रहे हैं। वड़िंग का राहुल के साथ संबंध उनके युवा कांग्रेस के दिनों से है। सन् 2014 में वड़िंग को भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था।

इस तरह पंजाब में राहुल के भरोसे और समर्थन से आगे बढ़े दो नेता आपस में लड़ रहे हैं और गांधी परिवार अपनी युवा पीढ़ी के एक तीसरे नेता, पायलट, पर भरोसा कर रहा है कि वे दोनों को नियंत्रण में रखेंगे।

पायलट के लिए इस जिम्मेदारी का एक और पहलू है। बहुत कम कांग्रेस नेता इस बात को उतना करीब से जानते हैं कि लंबे समय तक चलने वाली अंदरूनी लड़ाई राजनीतिक करियर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ उनकी अपनी लड़ाई कांग्रेस सरकार पर हावी रही और आखिरकार राज्य में भाजपा के साथ पार्टी की लड़ाई जितनी ही महत्वपूर्ण हो गई। इसलिए पंजाब, पायलट को वह जिम्मेदारी दे रहा है, जिसकी उन्हें लंबे समय से इच्छा रही है, ऐसी राजनीतिक जिम्मेदारी, जिसके नतीजे साफ तौर पर मापे जा सकें।

जब 2028 में राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव आएगा, तब इसका बहुत महत्व हो सकता है। राजस्थान में नेतृत्व पर पायलट का दावा और मजबूत होगा, अगर वे यह साबित कर पाते हैं

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सत्य निकेतन हादसा, बिल्डिंग की मालकिन, पति व पुत्र गिरफ्तार

नई दिल्ली, 07 सितंबर। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत ढ हने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मकान मालिक के परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संपत्ति की मालकिन उर्मिला गुप्ता (75), उनके पति हरिराम गुप्ता (81) और बेटे महेश गुप्ता (52) को गिरफ्तार किया है। हादसे के बाद चलाए गए लंबे बचाव अभियान में मलबे के नीचे दबे कुल 12 लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से सात लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच घायल अस्पताल में भर्ती हैं। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में जान गंवाने वालों में ज्यादातर युवा छात्र थे।

- हादसे में जान गंवाने वाले 7 लोगों में 6 युवक थे।

राहुल की यात्रा से पूर्व पायलट को पंजाब की खेमेबाजी का समाधान निकालना है

जिम्मेवारी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि, राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मु.मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ, एक बड़े खेमे का नेतृत्व कर रहे हैं

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। पंजाब कांग्रेस में हुए फेरबदल ने पार्टी की प्रदेश इकाई को न केवल हैरान किया है, बल्कि यह स्पष्ट संदेश भी दिया है कि केन्द्रीय नेतृत्व के पास जानकारी हासिल करने की अपनी निजी व्यवस्था भी है और वह किसी एक व्यक्ति की राय पर निर्भर नहीं है।

कांग्रेस हाईकमान ने भूपेश बघेल को पंजाब भेजा था, तथा उन्हें गुटों में बँटी प्रदेश कांग्रेस को एकजुट करने की विशेष जिम्मेदारी दी गई थी। अब बघेल को पंजाब से हटा दिया गया है और उनकी जगह सचिन पायलट को यह जिम्मेदारी दी गई है।

पंजाब के नये प्रभारी सचिन पायलट ने राजस्थान में भी इसी तरह की गुटबाजी का सामना किया है और वे अच्छी तरह समझते हैं कि इससे पार्टी को कितना नुकसान होता है।

- साथ ही यह भी विदित है कि राजस्थान के प्रभारी के रूप में रंधावा को गहलोत समर्थक माना जाता है।

एक खास दिलचस्प बात यह है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो इस समय चन्नी खेमे में एक प्रमुख नेता हैं, पायलट के गृह राज्य राजस्थान के प्रभारी हैं।

अब पायलट की जिम्मेदारी होगी कि वे रंधावा को चन्नी खेमे से अलग करके अपने साथ लाएं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पंजाब के सभी गुटों में पायलट को स्वीकार किया जाता है और हाईकमान के इस फैसले का पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं, दोनों ने स्वागत किया है।

अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पायलट के सामने, राहुल गांधी के पंजाब दौरे से पहले, सभी नेताओं को एकजुट करने की चुनौती है, ताकि एकता का माहौल बनाया जा सके और जनता को यह संदेश दिया जा सके कि अंदरूनी बदलावों के बाद ''सब चंगा सी'', यानी सब कुछ ठीक है।

फिलहाल एक गुट का नेतृत्व चरणजीत सिंह चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा कर रहे हैं, जबकि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अपने-अपने अलग गुटों का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, राजा वड़िंग को जिला अध्यक्षों का भी समर्थन हासिल है, क्योंकि उन्हीं ने उनकी नियुक्तियां की थीं।

प्रभारी के रूप में बघेल से उम्मीद की गई थी कि वे इन गुटों को एक साथ लाकर पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन वह इस काम में सफल नहीं हो सके और उन पर आरोप लगा कि वे खुद ही एक अलग गुट बन गए थे।

'प्रभारी' की जिम्मेदारी आमतौर पर किसी दूसरे राज्य के नेता को इसलिए दी जाती है, ताकि वह स्थानीय स्थिति को नए नजरिए से देख सके।

कांग्रेस हाईकमान को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में बघेल ने यथास्थिति बनाए रखने की सिफारिश की थी और, खास तौर पर, राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बनाए रखने की बात कही थी।

दिल्ली में संगठन प्रभारी के साथ हुई बैठक में, चन्नी और रंधावा ने वड़िंग को हटाने की मांग की थी।

इस बीच, राहुल गांधी के पंजाब के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सेनाओं के लिये 1.10 लाख करोड़ रु. की खरीद को मंजूरी

नई दिल्ली, 07 सितंबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) की बैठक में तीनों सेनाओं के लिए लगभग एक लाख 10 हजार करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इससे भारतीय सेना के लिए केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेकी व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल, सेल्फ-प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद की जाएगी। मंजूर किये गए प्रस्तावों में से लगभग 98 फीसदी खरीद भारतीय इंडस्ट्री से की जाएगी।

रक्षा बलों के अलग-अलग अधिग्रहण प्रस्तावों को आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन), यानी सैद्धांतिक एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी मिलने से तीनों सेनाओं को नए हथियार मिलने से युद्धक क्षमता मजबूत होगी। सेना के लिए खरीदे जाने वाले केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेकी व्हीकल प्रभावित क्षेत्र का पता लगाने, पहचानने, मॉनिटर करने और मार्किंग करने में सक्षम होंगे।

सरकार को अविलंब आना पड़ा, इसरो के स्टाफ की आशंका दूर करने के लिए

स्टाफ में आशंका का कारण था, ''इन-स्पेस'' के अध्यक्ष पवन गोयंका का वह वक्तव्य जिसमें उन्होंने कहा था कि ''इसरो अब कोई लॉन्च व्हिकल्स'' नहीं बनाएगा। यह सारा काम अब प्राइवेट सैक्टर व प्राइवेट पार्टियों के लिए छोड़ दिया जाएगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 सितम्बर। मोदी सरकार ने देश की अंतरिक्ष एजेंसी ''इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो)'' के काम के तेजी से हो रहे निजीकरण को लेकर उसके कर्मचारियों के बढ़ते हुये डर, बेचैनी और चिंता को शुरू में ही खत्म करने की कोशिश की है। कुछ निजी कंपनियों को काम करने के लिए लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं।

सूत्रों ने बताया कि सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने इसरो से एक बयान जारी करने को कहा, जिसमें कहा जाए कि इसरो देश की प्रमुख अंतरिक्ष संस्था बनी रहेगी। यह कदम इसरो के कर्मचारी संगठनों द्वारा इसरो कुछ गतिविधियों को निजी और सरकारी कंपनियों को सौंपने की योजनाओं पर चिंता जताए जाने के बाद उठाया गया।

केन्द्र सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब विपक्ष मोदी सरकार की संवेदनशील और रणनीतिक तकनीकों को निजी क्षेत्र को सौंपने की योजना का विरोध कर रहा है। कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने इसरो के कथित निजीकरण को तुरंत रोकने की मांग की है।

- पवन गोयंका का इशारा था कि इसरो अब भविष्य में स्पेश रिसर्च व नई-नई टैक्नॉलजी विकसित करने की आर एण्ड डी का ही काम करेगा।

विपक्ष का विरोध ''आईएन-स्पेस'' के अध्यक्ष पवन गोयनका के उस बयान के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ''आखिरकार इसरो कोई भी प्रक्षेपण यान न तो बनाएगा और न ही उसका निर्माण करेगा'' और इसका पूरा उत्पादन सरकारी उपक्रमों या निजी कंपनियों को पूरी तरह सौंप दिया जाएगा।

गोयनका के इस बयान के बाद, इसरो के नौ कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध पत्र जारी किया।

भारत अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी दुनिया के प्रमुख देशों में से एक है।

इसरो ने मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान भेजा है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास यान उतारा है और अपना खुद का प्रक्षेपण तंत्र यान विकसित किया है। वह देश की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान की भी तैयारी कर रहा है।

एजेंसी ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''इसरो उन्नत अंतरिक्ष अनुसंधान और तकनीक के विकास, राष्ट्रीय और रणनीतिक अभियानों, अंतरिक्ष विज्ञान और खोज तथा अंतरिक्ष की महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक क्षमताओं के लिए भारत का प्रमुख संस्थान बना रहेगा।

इस पोस्ट में उन आशंकाओं को दूर करने की भी कोशिश की गई कि संगठन का न तो निजीकरण किया जाएगा और न इसका महत्व ही कम किया जाएगा।

यह बयान 4 सितंबर को कर्मचारी संगठन के उस पत्र के बाद आया, जिसे मीडिया ने प्रकाशित किया था और ''रॉयटर्स'' ने भी देखा था। इसमें इसरो के कुछ कर्मचारियों ने इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन से उन खबरों पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिनमें कहा गया था कि वर्तमान में एजेंसी द्वारा संभाली जा रही निर्माण और संचालन की जिम्मेदारियां कंपनियों को सौंप दी जाएंगी।

पुलिस जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति पर 14 तक फैसला ले- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 07 सितंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि वह जंतर-मंतर पर आरक्षण और यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन करने की इजाजत देने पर 14 सितंबर तक फैसला ले। जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने ये आदेश दिया।

क्षत्रिय करणी सेना 20 सितंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहती है। कोर्ट ने क्षत्रिय करणी सेना से कहा है कि वह पुलिस को अपना आवेदन दे। पुलिस 14 सितंबर तक उस पर फैसला करेगी और आपको अपने फैसले की जानकारी देगी।